

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २७ दिसम्बर, 2011

विषय:—ग्राम पस्तौरा, तहसील एवं परगना जसपुर, जिला उधमसिंह नगर में राजकीय पोलिटेक्निक, जसपुर की स्थापना हेतु 2.023 है० भूमि, तकनीकी शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2194/सात—स०भ०३०/2011, दि०-१८-८-२०११ के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम पस्तौरा तहसील एवं परगना जसपुर, जिला उधमसिंह नगर में राजकीय पोलिटेक्निक, जसपुर की स्थापना हेतु उक्त ग्राम के खाता संख्या 70 के खसरा सं०-२०/०१ के अधीन 2.023 है० भूमि, वित्त अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या—२६०/वित्त अनुभाग-३/२००२ दिनांक १५-०२-०२ के प्राविधानों के अधीन तथा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- १— भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- २— जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- ३— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- ४— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या ३ वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- ५— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संरथा, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- ६— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशोष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- ७— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों के लिए नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ०प०संख्या-२४७७ / समदिनांकित / 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4— आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 5— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।
- 6— प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(संतोष बडोनी)
अनुसन्धित।